सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-29 अंक-6 22 मार्च से 5 अप्रैल, 2014 मुख्य संपादक कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com मूल्य : 2 रुपये

देश भर में मनाया गया 8 मार्च—अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

अमेरिका के न्यूयार्क शहर की कामकाजी महिलाएं पुरुषों के समान वेतन व काम के घण्टे 8 करने की मांगों को लेकर लम्बे अर्से से आन्दोलन कर रही थी। 8 मार्च 1908 को जब वे सड़कों पर उतरी तो अमेरिकी सरकार को यह रास नहीं आया। पुलिस ने उन पर गोलियां चलाई। न्यूयार्क की सड़के कामकाजी महिलाओं के खून से लाल हो गई। कामकाजी महिलाओं का यह संघर्ष बेकार नहीं गया। इसने दुनिया भर में प्रेरणा पैदा की। 1910 में कोपेनहेगन में अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी महिला सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें विख्यात समाजवादी नेता क्लारा जैटकिन ने 8 मार्च का दिन अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में बनाने का आह्वान किया। यह दिन महिलाओं की मुक्ति, सम्मान व समानता के लिए संघर्ष का मूर्त रूप बन गया है।

दिल्ली में सभा को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड छाया मुखर्जी

दिल्ली में महिलाओं और बच्चों पर बढ़ते अपराधों के खिलाफ धरना

8 मार्च को महिलाओं और बच्चों पर बढ़ते अपराधों के खिलाफ दिल्ली सचिवालय, आई.टी.ओ. पर ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन (ऑल इण्डिया एमएसएस) की दिल्ली राज्य कमेटी द्वारा एक धरने का आयोजन किया गया। धरने में दिल्ली के विभिन्न इलाकों से आई महिलाओं ने हिस्सा लिया। धरने के दौरान हुई सभा की मुख्य वक्ता थी ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन की अखिल भारतीय अध्यक्ष श्रीमती छाया मुखर्जी। अतिथि वक्ता के रूप में ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक स्टूडेन्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव कॉमरेड अशोक मिश्रा ने भी सभा को सम्बोधित किया। सभा की शुरूआत एस.यू.सी.आई.(सी) के दिल्ली राज्य सचिवमंडल सदस्य कॉ. आर.के.शर्मा द्वारा प्रस्तुत स्वरचित गीत 'नारी जाग जरा' के साथ हुई। सभा में अन्य वक्ता थी एआईएमएसएस की दिल्ली राज्याध्यक्ष प्रो. सुबोध शर्मा, उपाध्यक्ष एडवोकेट कुसुम सिंह, एडवोकेट दीपिका जैन व नीतू खन्ना, कमेटी सदस्य सीता सिंह, आशा रानी, स्मिता सिन्हा, संध्या विश्वकर्मा, रितु गिरी, डॉली शर्मा, चित्रा सिंह, साधना। सभा का संचालन एआईएमएसएस की दिल्ली राज्य सचिव कॉ. रितु कौशिक ने किया।

वक्ताओं ने कहा कि आज महिलाओं और बच्चियों पर बढ़ते अपराधों ने सारी हदें पार कर दी हैं। विभिन्न जनविरोधी नीतियों के चलते पूरा समाज ही सांस्कृतिक पतन का शिकार हो रहा है। भूमण्डलीकरण, निजीकरण व उदारीकरण की जनविरोधी नीतियों के चलते महिलाओं को उपभोग की वस्तु में रूपांतरित किया जा रहा है। इस रुझान की सबसे भद्दी अभिव्यक्ति तथाकथित सौन्दर्य-प्रतियोगिताओं व प्रदर्शनियों के बढ़ते प्रचलन के रूप में हुई है। उपभोक्तावादी संस्कृति को फैलाने के लिए भी नारी को ही निशाना बनाया जा रहा है। यौन-पर्यटन, सेक्स और हिंसा को तरह-तरह के संचार माध्यमों द्वारा महिमामंडित करना, साइबर अपराध, महिलाओं पर नये-नये तरीके की हिंसा जिसमें उन पर तेजाब फेंकना भी शामिल है, रेडियो, टी.वी. व अन्य प्रचार माध्यमों से खुलकर अश्लीलता परोसी जा रही है। बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, यहाँ तक कि बलात्कार

(शेष पृष्ठ 2 पर)

आरएमपी, एसयूसीआई(सी) और एमसीपीआई(यू) ने केरल में गठित किया लेफ्ट युनाइटेड फ्रण्ट

भूमण्डलीकरण की नीतियों, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता तथा हिंसा की राजनीति के खिलाफ संयुक्त जनवादी आन्दोलनों के निर्माण का आह्वान

केरल में तीन वामपंथी पार्टियों रिवोल्यूशनरी मार्क्सवादी पार्टी (आरएमपी) एसयूसीआई(सी) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (यूनाइटेड) यानी (एमसीपीआई(यू)) का एक राज्य स्तरीय संयुक्त मोर्चा लेफ्ट यूनाइटेड फ्रण्ट (एलयूएफ) गठित किया गया है। इसका घोषित लक्ष्य केन्द्र और राज्य सरकारों की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ तथा भूमण्डलीकरण, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता और विशेषकर हिंसा की राजनीति के खिलाफ लोगों के संयुक्त जनवादी आन्दोलनों का निर्माण करना है।

सीपीआई(एम) नेतृत्व के मजदूर वर्ग-विरोधी-रूख रवैए के खिलाफ बगावत करते हुए उस पार्टी को छोड़ने वाले नेताओं और कैडरों के एक ग्रुप ने कुछ वर्ष पहले एमसीपीआई(यू) का गठन किया था। सीपीआई(एम) नेतृत्व से कुछ नीतिगत सवालों पर मतभेद को लेकर हॉल ही में पार्टी छोड़ने वाले नेताओं और कैडरों के एक अन्य ग्रुप ने आरएमपी गठित की है। सीपीआई(एम) राज्य नेतृत्व द्वारा भाड़े के हत्यारे लगा कर आरएमपी के संस्थापक नेता कॉमरेड टी.पी. चन्द्रशेखरन की बेरहमी से हत्या करवा दी गई। आगामी लोकसभा चुनाव में एलयूएफ राज्य की 20 सीटों में से 18 सीटों पर उम्मीदवार मैदान में उतारेगा जिनमें से 5 पर एसयूसीआई (सी) 3 पर एमसीपीआई(यू), 9 पर आरएमपी और एक एलयूएफ द्वारा समर्थित आजाद उम्मीदवार होगा। हमारी पार्टी के उम्मीदवार त्रिवेद्रम से (एम. शजर खान), पत्तनमथिट्टा से (एस. राधामणि), मवेलिक्कारा से (के. एस. शशिकला), अलापुड़ा से (एडवोकेट एम ए बिन्दु) और कोट्टयम (एन के बीजू) चुनाव लड़ेंगे।

12 मार्च 2014 को अलापुड़ा के एश्वर्य ऑडिटोरियम में एलयूएफ के गठन की घोषणा करते हुए एक राज्य

(शेष पृष्ठ 7 पर)

सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड सी के लुकोस

सम्मेलन के बाद हुए विशाल प्रदर्शन का एक दृश्य

8 मार्च....

(पृष्ठ 1 का शेष)

के बाद हत्या, यौन उत्पीड़न के अपराधों को नजरअंदाज कर पुलिस-प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही न होने के कारण ऐसी आपराधिक मनोवृत्ति को संरक्षण मिल रहा है जिसके चलते अपराधी सीना तान कर खुलेआम घूमने की छूट पा चुके हैं। राजधानी दिल्ली में पिछले वर्ष 635 बलात्कार की घटनाएँ दर्ज हुई हैं। दिल्ली में 16 दिसम्बर 2012 को हुई सामूहिक बलात्कार की घटना जिसमें एक छात्रा के साथ 6 दरिंदों ने वीभत्स आचरण व बलात्कार किया था तथा उसे मौत की नींद सुला दिया था। उस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। लेकिन सरकार फिर भी होश में नहीं आई। सरकार द्वारा नशाखोरी व अश्लीलता को खुला बढ़ावा दिया जा रहा है जो समाज को गर्त में ले जाने वाले कदम हैं। यह सर्वविदित है कि अपराधों में वृद्धि करने में शराब व नशाखोरी की भारी भूमिका है। लेकिन फिर भी शराब की दुकानों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है।

वक्ताओं ने कहा कि इन समस्याओं के खिलाफ देशभर में एक जबरदस्त प्रतिरोध आंदोलन गठित करने की जरूरत है। उन्होंने देश के छात्र-नौजवानों, विशेषकर महिलाओं से आह्वान किया कि वे इन सब आंदोलनों को मजबूत बनाते हुए सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन को आगे बढ़ाएं।

उत्तर प्रदेश में जगह-जगह हुए कार्यक्रम

इलाहाबाद : 8 मार्च को अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ऑल इण्डिया एमएसएस ने अल्लापुर में तुलसी मंच पर एक सभा का आयोजन किया। 'महिलाओं पर बढ़ते अपराध के खिलाफ संघर्ष को मजबूत कीजिये' और 'अश्लीलता, अपसंस्कृति, नशाखोरी पर रोक के लिये सरकार को मजबूर करें' के नारे के साथ महिलाओं को बैज पहनाने का एक कार्यक्रम भी रखा गया।

आल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन की प्रदेश संयोजिका रश्मि मालवीय ने कहा कि 8 मार्च न तो कोई उत्सव की तरह मनाने का दिवस है और न ही कोई कर्मकाण्ड है। बल्कि शोषण-उत्पीड़न की शिकार दुनिया भर की औरतों के सम्मान, उनके अस्तित्व के लिये संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिये शपथ लेने और आम औरत की लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिये प्रेरणा देने वाला यादगार दिन है।

कल्याणी रायचौधरी ने कहा कि महिलाओं को व्यक्तिगत लड़ाई और स्वार्थ को छोड़ कर महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा के लिये संगठित होना, आज की सबसे बड़ी जरूरत है। संगठित लड़ाई ही उनको समाज में मजबूत बनाएगी।

सभा को लता शर्मा, राजेश्वरी श्रीवास्तव, ज्ञानशीला शर्मा, रेनू गुप्ता, संध्या मिश्रा ने भी संबोधित किया। प्रियंका सिंह ने 'तेरा हुआ है क्यों ये हाल, नारी सोच जरा' जैसे गीतों से माहौल को संवेदनशील बना दिया। सभा का संचालन डॉ. झरना मालवीय ने किया।

मुरादाबाद (यू.पी.) : 9 मार्च को ''8 मार्च अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस'' के अवसर पर आई.एम.ए. हॉल, मुरादाबाद में एआईडीवाईओ, एआईडीएसओ तथा एआईएमएसएस द्वारा शानदार नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता एआईडीवाईओ के प्रदेश अध्यक्ष कॉ. हरकिशोर सिंह ने की तथा संचालन एआईडीएसओ की जिला अध्यक्षा कॉ. ऋतु चौधरी ने किया।

वसुंधरा में सभा को सम्बोधित करती हुई कॉ. रितु कौशिक

सम्मेलन की शुरूआत सांस्कृतिक कार्यक्रम से हुई जिस में कथक नृत्य तथा महिला अपराध और कन्या भ्रूण हत्या विरोधी नृत्य गाने और कविताएं प्रस्तुत की गई। प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका बाल सुन्दरी तिवारी ने वादन के साथ महिलाओं को प्रेरित करने वाले तथा जागृत करने वाले गीत प्रस्तुत किए।

सम्मेलन को मुख्य वक्ता के रूप में एआईडीएसओ के राष्ट्रीय महासचिव कॉ. अशोक मिश्रा ने सम्बोधित किया। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस को समर्पित कविता ''मैं ठिकाना ढूँढ़ रही हूँ'' प्रस्तुत की। उन्होंने आगे कहा कि बीते 30 दिसम्बर 2013 को कड़कड़ाती ठण्ड में हजारों छात्र-नौजवानों और महिलाओं ने जन्तर-मन्तर नई दिल्ली में एकत्र होकर 'दामिनी' को याद किया। चार्ल्स डिकेन का कथन है कि यह सबसे खराब समय है और सबसे अच्छा समय भी है। खराब समय इसलिए है कि अन्याय-अत्याचार हो रहा है, इन्सान में से इन्सानियत खत्म हो रही है। लेकिन साथ ही अन्याय-अत्याचार के खिलाफ जुझारू आन्दोलन चल रहा है। इसलिए अच्छा समय है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अन्तिम सांस तक इन्सान की तरह जीने का अधिकार मिलना चाहिए, इसका मतलब ही है कि उसे शिक्षा पाने का अधिकार हो सिर्फ कक्षा-8 या कक्षा-5 तक नहीं जैसा कि ''सर्व शिक्षा अभियान'' में कहा गया है। सरकार कहती है कि शिक्षा देना अब सरकार का काम नहीं है। नई शिक्षा नीति1986 में साफ कर दिया कि जनता की शिक्षा जनता की जिम्मेदारी है। एनडीए सरकार के शासन काल में बनाए गए बिड़ला अम्बानी शिक्षा कमीशन ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार का काम शिक्षा देना नहीं है। शिक्षा का बाजार पूँजीपतियों को मुनाफा कमाने के लिए दे दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने 2009 से शिक्षा पर टैक्स लगा दिया और लोग जो भी चीज खरीदते हैं उस पर 3% शिक्षा टैक्स देना पड़ता है। इसमें से 2% प्राइमरी शिक्षा के लिए 1% उच्च शिक्षा के लिए देना होता है। शिक्षा के लिए टैक्स आप लोग दे रहे हैं और उसी पैसे से पूँजीपति शिक्षा को बेच कर मुनाफा कमा रहे हैं। यूजीसी के चेयरमेन ने कोयमबटूर में ऐलान किया कि सरकार पचास हजार करोड़ रुपये शिक्षा के लिए देगी जिसमें 50% यानी पच्चीस हजार करोड़ रुपया निजी संस्थानों को देंगे। शिक्षा के निजीकरण के कारण शिक्षा में भारी भ्रष्टाचार पैदा हो गया है तथा शिक्षा व्यापारी/पूँजीपति व मंत्री मिलकर एक बड़ा शिक्षा माफिया का आपराधिक गठजोड़ पैदा हो गया है। गुजरात के पाटन कॉलेज के एक छात्रा की कॉलेज के मैनेजमेण्ट व स्टॉफ ने मिलकर बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी। उड़ीसा में फीस वृद्धि के खिलाफ एक छात्रा ने आवाज उठाई तो उसका अपहरण करके खुले आम बलात्कार के बाद हत्या कर दी। आप के शहर मुरादाबाद में प्राइवेट कालिजों में भी इस प्रकार की घटना हो रही हैं। उन्होंने सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा के बयान ''बलात्कार नहीं रोक सकते तो उसका मजा लीजिए'' की कड़े शब्दों में निन्दा की तथा सभी का आह्वान किया ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि आज शिक्षा को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है। इसके खिलाफ आवाज बुलन्द करने के लिए हम लोग पूरे देश में आन्दोलन संगठित कर रहे हैं।

आज भूमण्डलीकरण के इस युग में महिलाओं पर जबरदस्त हमला हो रहा है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि पूँजीवाद में महिलाएं सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली वस्तुएं हैं और आज वही बात सही साबित हो कर महिलाएं पूँजीपतियों का सामान बेचने का सबसे बड़ा यन्त्र बन गई हैं। इन सबके खिलाफ उन्होंने उच्च आदर्श और नीति नैतिकता के साथ संघर्ष करने का आह्वान किया और कहा कि आज का दिन यह अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोगों को पुकार रहा है कि महिलाओं पर बढ़ रहे अपराधों के खिलाफ हम जुझारू आन्दोलन गठित करें।

सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में जाने माने साहित्यकार नवगीत कार डा. माहेश्वर तिवारी ने कहा कि आज का यह नागरिक सम्मेलन ऐतिहासिक है। मैंने इतनी गम्भीरता व अनुशासन कहीं नहीं देखा है। उन्होंने सम्मेलन में प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम को बहुत उच्च स्तर का बताया तथा सभी प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने इसी प्रकार के प्रेरणादायक कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित करने की अपील की। सम्मेलन को जाने माने चित्रकार व महाराजा हरीशचन्द्र डिग्री कॉलेज के प्रो. डॉ. चन्द्रभान यादव, मशहूर शायरा व चिकित्सक डॉ. मीना, राजकला गर्ल्स इण्टर कालेज की पूर्व प्राचार्या डॉ. अरुण लता रस्तोगी, शिक्षा अधिकारी बबीता सिंह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश महासचिव शशिबाला, एआईएमएसएस की माया राजपूत, कमलेश चहल आदि ने सम्बोधित किया।

सम्मेलन में हिन्दू डिग्री कॉलेज की वनस्पति विज्ञान की प्रोफेसर तथा कॉलेज की महिला सेल प्रभारी डॉ. बीना कुमारी, सुखदेवी इण्टर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री परम सिंह, जाने माने कवि वीरेन्द्र सिंह बृजवासी, रघुराज सिंह ''निष्चल'', अशोक विश्नाई, रामदत्त त्रिवेदी, ओमकार सिंह ''ओमकार'', रविशंकर चतुर्वेदी, शिशुपाल सिंह ''मधुकर'' उच्च प्राथमिक शिक्षक संघ की ब्लाक मुरादाबाद सचिव राजबाला दीक्षित, जूनियर हाई स्कूल की प्रधानाचार्या नीलम शर्मा एआईयूटीयूसी के राज्य सचिव विजय पाल सिंह, मुनीश चन्द्र त्यागी चिकित्सक डॉ. आजाद, विनोद बिग, राजेन्द्र सिंह, एडवोकेट आदि लगभग 200 नागरिक उपस्थित थे। सम्मेलन में सर्वसम्मति से दो प्रस्ताव पास किए गए।

प्रथम प्रस्ताव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा वर्करों व हैल्परों, बाल श्रम अनुदेशिकाओं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने वाली टीचरों आदि महिला कामगारों को सरकारी कर्मचारी घोषित कर पूरा वेतन व सम्मान देने तथा महिलाओं विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग भारत सरकार से की गई।

दूसरा प्रस्ताव मुरादाबाद शहर के चर्चित सतेन्द्र रस्तोगी सर्राफ की पुलिस कर्मियों द्वारा की गई हत्या के बारे में रखा गया। जिसमें सर्राफ के हत्यारे एसएचओ की गिरफ्तारी तथा सर्राफ की विधवा को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई।

मुरादाबाद की एमबीबीएस छात्रा नीरज भड़ाना के बलात्कार व हत्याकाण्ड के सम्बंध में जो मूल प्रस्ताव इस सम्मेलन में रखा जाना था वह नहीं रखा जा सका। इस मामले में मुरादाबाद के टीएमयू के कुलाधिपति सुरेश जैन व उसके पुत्र मनीष जैन नामजद अभियुक्त हैं तथा अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके लिए मुरादाबाद में लम्बे समय से आन्दोलन चल रहा है। ठीक 11 बजे जैसे ही कार्यक्रम शुरू हो रहा था तथा मुरादाबाद के विख्यात चित्रकार डॉ. नरेन्द्र सिंह की इस घटना के सम्बंध में बनाई गई पेंटिंग लगाई गई, नीरज भड़ाना का फोटो तथा आन्दोलन की प्रदर्शनी लगाई गई, आईएमए के पदाधिकारियों ने शिक्षा माफिया तथा हत्यारे सुरेश जैन के दबाव में हाल में कार्यक्रम आयोजित कराने में असमर्थता जता दी। लोगों में रोष व्याप्त हो गया। कोई और विकल्प न देख पेंटिंग सहित सभी प्रदर्शनी हटा कर

(शेष पृष्ठ 6 पर)

भ्रष्टाचार : सर्वव्यापी परजीवी

पूँजीवाद ही इसे जन्म देता है, पालता-पोसता है और इस पर आश्रित रहता है

भ्रष्टाचार अचानक देश में एक जीवन्त मुद्दा बन गया है। अब तक, कई सालों से पूरे समाज में एक शातिराना प्रचार चलाया जा रहा था। इस देश में जहाँ जनता को प्रत्यक्ष और परोक्ष हर तरीके से अपने जीवन को नसीब से जोड़ना सिखाया जाता है, इस प्रचार अभियान ने लोगों को यह स्वीकार करने की ओर प्रवृत्त किया कि भ्रष्टाचार उनके जीवन का, सामाजिक-राजनैतिक-सांस्कृतिक-आर्थिक गतिविधि के हर क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है। वे यह देखने के आदी से हो गये हैं कि सभी राजनैतिक पार्टियां, चाहे वे राष्ट्रीय हों या क्षेत्रीय, दक्षिणपंथी हों या वामपंथी चोगे वाली, केन्द्र या राज्यों में विधायिका के सदनों में सत्तापक्ष और विपक्ष की भूमिका की अदलाबदली करती रहती हैं जो कि ढर्रा बन गया है। जब विपक्ष में होती है तो उन्हें सुविधा होने पर गाहे-बगाहे वे सत्तासीन पार्टी के भ्रष्टाचार के विरुद्ध जहर उगलती रहती है। फिर जैसे ही वे खुद सत्ता पर काबिज हो जाती है तो वे भी भ्रष्टाचार मचाती है जिसकी उन्होंने पहले आलोचना की थी और अब विपक्ष की ओर से उसी तरह के हमलों को झेल रही होती जो एक समय उन्होंने खुद किये थे।

इस प्रकार, आजादी के बाद से कई दशकों तक शासक पूँजीपति वर्ग की सबसे भरोसेमंद प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस सरकारी सत्ता में रही, इसने भ्रष्टाचार से कभी गुरेज नहीं किया, साथ ही इसके खिलाफ शोर भी मचाती रही। आजादी के तुरन्त बाद सन 1948 में, जीप-घोटाला हुआ जिसमें कांग्रेस के नेता घूसखोरी में संलिप्त थे। सन 1949 में केन्द्रीय उद्योग मंत्री को इसी प्रकार के अपराध के लिए हिरासत में लिया गया; सन 1958 में, तत्कालीन वित्त मंत्री को एलआईसी घोटाले में इस्तीफा देना पड़ा; इन्दिरा गाँधी के शासनकाल में सत्तर के दशक के अन्तिम दौर में सांघातिक भ्रष्टाचार को जयप्रकाश नारायण के सुविख्यात आन्दोलन का एक अन्यन्य प्रमुख मुद्दा बनाया गया था; बोफोर्स घोटाले ने राजीव गांधी के शासन की शोभा बढ़ाई थी; शेयर घोटाला करने वाले कुख्यात स्टॉक मार्केट एजेण्ट हर्षद मेहता द्वारा कथित तौर पर नरसिम्हा राव को एक नोटों से भरा हुआ सूटकेस प्रदान किया गया था।

लेकिन कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार के शासनकाल में जो उभर कर आए, उन एक पर एक हुए महाघोटालों के साए में पुराने घोटालों के सभी रिकार्ड निश्चित रूप से धुंधले पड़ गये लगते हैं। जहाँ 2011 में भौंचक्का कर देने वाला 2जी स्पैक्ट्रम घोटाला हुआ जिसमें खबर है कि व्यक्तिगत फायदों के लिए जनता के धन के कुल मिलाकर 1.77 लाख करोड़ रुपये (1766.45 बिलियन) उड़ा दिये गये। इसमें केंद्रीय मंत्री और केन्द्र में कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार की एक सहयोगी डीएमके पार्टी के सांसद सहित राजनीतिज्ञ और सरकारी अफसर मुख्य रूप से शामिल थे। सन 2012 में कोयला निलामी घोटाला हुआ जो कोलगेट घोटाले के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कोयला खदानों को बिना किसी निलामी के ही आबंटित कर दिया गया और पब्लिक सैक्टर एण्टरप्राइजेज़ और प्राइवेट फर्मों ने उससे कम कीमत अदा की जो उन्हें निलामी के बाद करनी पड़ती। इस वजह से सरकारी खजाने को 1.86 लाख करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा। इसी के साथ-साथ प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कागजातों में हेरा-फेरी हुई। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी द्वारा संसद में इस बेकायदा हरकत की बेशर्मी से हालांकि कमजोर पैरवी भी की गई। फिर लगभग 32000 करोड़ रुपये के जाली गैर-न्यायिक स्टॉम्प पेपरों की छपाई करके सरकारी राजस्व के गबन का तेलगी घोटाला हुआ। यह सिद्ध करता है कि विभिन्न पार्टियों के मुख्यमंत्री के स्तर के राजनीतिज्ञों या विधायकों और आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र के अग्रणी राजनीतिज्ञों तथा आला अफसरों और पुलिस के आला अफसरों की सह-अपराधिता और संरक्षण के बल पर ऐसा हुआ, इसके बिना यह जाली कागजात की छपाई का कार्य नहीं हो पाता। खेल-कूद के क्षेत्रों में भी बहुत बड़े-बड़े घोटाले हुए थे जैसे बहु चर्चित कॉमनवैल्थ गैम्स घोटाला और आईपीएल घोटाला जिसमें कांग्रेस के एक केन्द्रीय मंत्री समेत कुछ बड़े नेता भी शामिल थे। महाराष्ट्र में आदर्श हाऊसिंग घोटाला हुआ जिसमें कांग्रेस के वर्तमान केन्द्रीय गृह मंत्री, कांग्रेस के पूर्व विधान परिषद सदस्यों(एमएलसी) सहित महाराष्ट्र के अलग-अलग समय और अलग-अलग पार्टियों के चार मुख्यमंत्रियों की विशिष्ट मंडली, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, कर्नल व अन्य रैंकों के बहुत से सेवानिवृत्त आर्मी अफसर, आईएएस अधिकारियों, सचिवों समेत अफसरशाह आदि रिहायशी अपार्टमेण्टों की खरीदारी सम्बन्धी मनी लांड्रिंग (काला धन निवेश) करते पाए गए। इसी प्रकार के अन्य कई घोटाले हुए।

कांग्रेस के कीर्तिमान इतने 'वांछनीय' हैं कि ये कांग्रेस को देश में घोटालों के सरताज के तौर पर नवाजते हैं और मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा को कांग्रेस के विरुद्ध सम्पूर्ण शस्त्रागार के साथ हमला करने में मदद पहुँचाते हैं। लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी भी जब वह सत्ता से बाहर थी और भाजपा-नीत एनडीए के हाथ में कुछ दिन केन्द्र सरकार की बागडोर थी, तब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा पर झपटने से नहीं हिचकिचाई। भाजपा के कई घोटालों को सतह पर लाने के लिए इसका वह संक्षिप्त कार्यकाल ही काफी था, जैसे उनके पार्टी अध्यक्ष एक स्टिंग ऑपरेशन में घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए; भाजपा मुख्यमंत्री पर अपने निकटतम परिजनों द्वारा संचालित एक ट्रस्ट के लिए ढेर सारा ''चन्दा'' लेने के लिए खदान कम्पनियों पर अनावश्यक कृपादृष्टि दिखाकर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा; बात इस हद तक बढ़ गयी थी कि उन्हें भाजपा से निष्कासित करना पड़ा, हालांकि थोड़े ही दिन पहले उन्हें फिर बहाल कर दिया गया। फिर एनडीए के केन्द्रीय राज्य मंत्री ने अपने सरकारी निवास के मनोहर नवीकरण में हुए बड़े भारी खर्च का एक बिल भारतीय उड्डयन प्राधिकरण के खाते में दिखाया जिसमें फर्नीचर, मोबाइल टेलिफोन, ग्रीटिंग कार्ड आदि के अलावा 2,26,600 रुपये की एक पेण्टिंग और एक फव्वारा भी शामिल थे। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भी, जो कि गुजरात के सन 2002 के अल्पसंख्यक-विरोधी सामूहिक हत्याकाण्ड के रचियता हैं और वर्तमान में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, जिनको देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के नेतृत्वकारी एकाधिकारी पूँजीपति प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उनकी सुयोग्यता के लिए, ईमानदारी और निपुणता के लिए बार-बार चुने हुए विशेषणों की झड़ी लगा रहे हैं, लेकिन यह सब गुजरात के कम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल (कैग) की उस रिपोर्ट को नहीं मिटा सकता जो कुछ मुट्ठीभर कॉरपोरेटों को फायदा पहुँचाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र अंडरटेकिंग का दुरुपयोग करने के सुविदित आरोपों के बीच कई प्रोजेक्टों में लगभग 17,000 करोड़ रुपये की अनियमितता की ओर इशारा करती है।

इस प्रतिस्पर्धा में क्षेत्रीय बुर्जुआ पार्टियाँ भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में विपक्ष में बैठी बसपा भ्रष्टाचार के लिए सत्तापक्ष में बैठी सपा पर उंगली उठाती है; जबकि सपा भी बसपा और उसकी सुप्रीमो मायावती के शासनकाल में एक पर एक हुए घोटालों के लिए उसे नहीं बख्शती है। पश्चिम बंगाल में जहाँ सीपीएम ने भ्रष्टाचार को वस्तुत: एक संगठित ढंग से संस्थागत रूप दिया वह अब शासक टीएमसी के खिलाफ शोरगुल मचा रही है। इसी तरह जब सीपीएम शासन में थी तब टीएमसी उसके खिलाफ जहर उगलती रहती थी। भ्रष्टाचार के संस्थानीकरण द्वारा अब ऐसा लगता है कि शासक टीएमसी ने वैधानिक झांसापट्टी में एक नई गहराई हासिल कर ली है। मुख्यत: हाल ही में पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की सीटों के लिए हुई क्रोस-वोटिंग में कथित रूप से धन और सुविधा के प्रलोभन ने एक अहम भूमिका अदा की। पीछे से एक अवास्तविक सैद्धान्तिक मुलम्मा चढ़ाकर टीएमसी एकदम घृणित ढंग से विपक्ष का सफाया सुनिश्चित करने के लिए विपक्ष से कुछ दलबदलू विधायकों के वोट खरीदती है, साथ ही राज्य में अब तक अनसुने राजनैतिक भ्रष्टाचार की शर्मनाक मिसाल कायम करती है।

दरअसल तथ्यात्मक बात यह है कि ये बुर्जुआ, पेटी-बुर्जुआ पार्टियाँ जिन्होंने देश की संसदीय प्रणाली में केवल सत्ता-सुख और धन के लिए जमघट लगा रखा है, जब वे सत्ता से बाहर होती हैं तो लोगों को लुभाने के लिए वे भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती हैं क्योंकि उन्हें सत्ता तक पहुँचने के लिए जन समर्थन और उनकी मंजूरी की जरूरत होती है। परन्तु जैसे ही वे अपने मिशन को हासिल करने में सफल हो जाती हैं तो वे अपने पहले वाले आचरण पर पहुँच जाती है और सरकारी एवं अन्य शक्तियों का मजे से इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं। फलस्वरूप जो पार्टियाँ सत्ता में होती हैं वे अपने आका, शासक पूँजीपति वर्ग, एकाधिकारी पूँजीपतियों या उनके संगी-साथियों की सेवा करती हैं और उनके द्वारा अपनाये गये भ्रष्ट तौर-तरीकों की ओर से आँख मूँद लेती हैं या अपनी धन-दौलत बनाने के लिए खुद भ्रष्टाचार करती हैं।

लेकिन लगता है कि हाल ही में सामान्य परिदृश्य को झकझोर दिया गया है। कुछ ही महीनों पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे और उनके लोगों के नेतृत्व में एक आन्दोलन हुआ था। भ्रष्टाचार की बीमारी और राजनीतिज्ञों और राजनीति को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने के शातिराना प्रचार ने जनता को इतना बेचैन बना दिया कि आन्दोलन जनमानस पर काफी प्रभाव डाल सका था। शुरूआत में अराजनैतिक घोषित किये गये आन्दोलन ने ही बुर्जुआ संसदीय राजनीति के अंधकारमय क्षेत्र में प्रकट होने के लिए एक नई राजनैतिक पार्टी को जन्म दिया। इसने जनता को आश्वासन दिया कि इसी व्यवस्था के अन्तर्गत ही भ्रष्टाचार को झाड़ू मार कर साफ किया जा सकता है और इस प्रकार इसने खड़ा होने के लिए एक नया आधार तलाशने और दिल्ली में एक नई सरकार बनाने के लिए उस पार्टी को चुनने के लिए जनता को लुभाया। इस पार्टी और इसकी सरकार के अस्तित्व में आने के कुछ ही दिनों के अन्दर इस पर अपने वादों से पीछे हटने के आरोप उनके अपने असंतुष्ट लोगों द्वारा लगाए गये। समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रचण्ड होती जा रही आवाज ने कुछ लोगों को कड़े कानून लागू करने की वकालत करने के लिए भी आगे बढ़ाया ताकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, खासकर सरकारी प्रशासन में इस बुराई की घुसपैठ पर रोक लगे।

फिर तो भारत के राष्ट्रपति से लेकर, जो अभी निकट अतीत में ही पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं में से एक थे, जिसे भी देखिए वही भ्रष्टाचार के खिलाफ आग उगलने लगा। राष्ट्रपति जी ने अपने पूर्व सहकर्मियों, राजनैतिक पार्टियों के नेताओं को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया तो वे चुनावों में हार का मुँह देखेंगे। कांग्रेस, मुख्य रूप से इसके द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत राहुल गांधी ने अब कॉरपोरेट प्रतिनिधियों के साथ अपनी मीटिंग में भ्रष्टाचार के विरुद्ध सुशासन का आश्वासन देते हुए जोशीला भाषण दिया। अथवा, दागी सांसदों को बचाने के लिए लाये गये अध्यादेश को फाड़ कर फेंक देने के लिए उन्होंने चीख-पुकार की, अवश्य ही इस बात की कोई व्याख्या दिए बिना कि वे उस समय क्या कर रहे थे जब यह अध्यादेश पारित किया गया या उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री 2जी स्पैक्ट्रम या कोलगेट जैसे घोटालों के प्रति मूक-बधिर बनकर क्यों बैठे हुए थे? अगले क्षण, उपरोक्त आदर्श हाऊसिंग घोटाले के खिलाफ तहकीकात की रिपोर्ट को अस्वीकार करने पर राहुल ने कांग्रेस-नीत महाराष्ट्र सरकार पर मुट्ठियाँ तानी। फिर, जो केन्द्रीय मंत्री औरों के साथ खुद भी आदर्श घोटाले में संलिप्त थे उनको अपनी पार्टी से निकालने के लिए उन्होंने अपने मुँह से एक भी शब्द भी क्यों नहीं बोला। यह समझना कोई मुश्किल नहीं था कि ये सभी भावभंगिमाएं चुनाव के उद्देश्य के लिए थी। आहिस्ता-आहिस्ता एकाधिकारी पूँजीपतियों की भाजपा के साथ घनिष्ठता बढ़ती जा रही है। यह एकाधिकारी पूँजीपतियों के कांग्रेस के प्रति फीके पड़ते समर्थन को

(शेष पृष्ठ 4 पर)

भ्रष्टाचार.....

(पृष्ठ 3 का शेष)

वापस पाने की एक सुनियोजित व्यग्र अपील थी। यह समान रूप से उन लोगों की खुशामद करने की एक कमजोर कोशिश थी जो भ्रष्टाचार और साथ ही एकाधिकारी पूँजीपति परस्त नीतियों के सवाल पर कांग्रेस से काफी दूर हो गए हैं। मोदी के हाथों में बैटन सौंप दिये जाने पर भाजपा नेता अब अपनी बारी आने पर कांग्रेस पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में असमर्थ होने और इसको बढ़ावा देने के आरोप लगा रहे हैं। दूसरी पार्टियाँ भी एक दूसरी पर इसी तरह के पैटर्न के हमलों की रूपरेखा तैयार कर रही हैं। साथ ही साथ वे मामले के परिपक्व होने के इंतजार में हैं ताकि उन्हें किसकी तरफ जाना है इसका फैसला करने में मदद मिल सके।

यह परिस्थिति एक ऐसे मोड़ पर पहुँच गई है कि सवालों की झड़ी सी लग गई है। क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा और इससे लड़ाई केवल चुनावों की हार-जीत से सम्बन्धित है? क्या यह सब कभी भ्रष्टाचार पर लगाम लगा पाएगा या नहीं इसका पता लगाने के लिए लोगों को एक बार फिर इंतजार करना चाहिए और चुनावों का आना-जाना देखना चाहिए, जैसा कि वे सालों से करते आये हैं? या उन्हें इस सर्वव्याप्त भ्रष्टाचार की उत्पत्ति और स्रोत को समझने के लिए गंभीरता के साथ थोड़ी और ज्यादा गहराई से खोज करने की बढ़चढ़ कर पहलकदमी करनी चाहिए और इससे लड़ने के लिए यथोचित उपचार्य रास्ता अपनाना चाहिए? भ्रष्टाचार समाज में आज इतना घातक क्यों हो गया है? क्या भ्रष्टाचार अनिवार्य रूप से राजनीति-राजनीतिज्ञों और राजनैतिक पार्टियों से सम्बद्ध है? क्या ऐसा विचार सावधानी से सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्रों, खासकर सत्ता के गलियारे की ओर जाने वाले अन्य रास्तों, जैसे एकाधिकारी पूँजीपति, मिलिट्री, नौकरशाह-कार्यपालिका, यहाँ तक कि न्यायपालिका को भी स्कैनर की पकड़ में आने से वर्जित नहीं कर देता है? जब सत्ता के तमाम गलियारों में, राजसत्ता रूपी तंत्र के सभी स्तम्भों में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें चौतरफा गहरी फैला चुका है, तब राजसत्ता को ही ज्यों का त्यों बरकारार रख कर क्या भ्रष्टाचार को पूरी तरह से मिटाया जा सकता है? कलम के जोर से कोई कानून तो गढ़ा जा सकता है। लेकिन क्या इस कानून को लागू किया जा सकता है अगर इस काम को करने की जिम्मेदारी जिस तंत्र को सौंपी गई है या जिससे अपेक्षा की जाती है कि कानून के राज की देखरेख करेगा या गलत काम करने वालों को सही रास्ते पर लायेगा जब वही इस बीमारी से पीड़ित हो। भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी एकमात्र राजनीति पर ही पूर्णरूप से डाल देना, निश्चित ही, शातिराना तौर पर लोगों में राजनैतिक-विरोधी, आन्दोलन-विरोधी मन बनाना है ताकि शासकों और गलत काम करने वालों को अपना कारोबार निर्विरोध चलाते रहने में मदद मिलती रहे।

हमने शुरूआत की थी कि संसदीय राजनैतिक पार्टियों ने क्या किया है और क्या कर रही हैं। साफ जाहिर है कि सरकारी सत्ता भ्रष्टाचार का एक लाभप्रद स्रोत और जरिया है। लेकिन भ्रष्टाचार में संलिप्त होना, करना और इसको बढ़ावा देना अपराध है तो भ्रष्टाचार करने के लिए उकसाना, इसका मूक दर्शक बने रहना, कुछ तुच्छ संकीर्ण स्वार्थों के लिए भ्रष्टों की ढाल बनना, एक भ्रष्ट सिस्टम या समूह की अगुआई करना और इससे दूसरी ओर मुँह फेर लेना भी समतुल्य अपराध है। इससे कार्यालय के तथाकथित ईमानदार मुखिया को अपनी जिम्मेदारियों और कर्त्तव्यों से छुटकारा नहीं मिल जाता है और उल्टे, उसे गलत काम करने वालों के खिलाफ उत्साहपूर्वक और सार्थक रूप से डटे रहना चाहिए। जब प्रधानमंत्री 2जी और कोलगेट घोटाले में अपने सहकर्मियों को बचाते हैं तब लोग लगभग उनको अलग से बेदाग नहीं पाते हैं। भ्रष्ट साथियों को रक्षा प्रदान करना ही अपने आप में एक भ्रष्ट कृत्य है। पाप करना और पाप की वकालत करना एक जैसी ही बात है। जब टीएमसी द्वारा संचालित धनाभावग्रस्त कोलकाता नगर निगम कोलकाता की सड़कों पर लगने वाली ट्राइडेण्ट बत्तियों की खरीदारी में टेण्डर छोड़ने में घोर अनियतिताओं और अत्यधिक महंगी दरों पर खरीदारी के आदेश देने के घपले में संलिप्त हो, तो पश्चिम बंगाल की प्रकट रूप से ईमानदार मुख्यमंत्री और टीएमसी पार्टी की अविवादित सुप्रीमो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाती हैं। जाहिर है कि इस तरह के कृत्य और कुछ नहीं बल्कि अपराधों को ढकने के प्रयास हैं। जब कोई एकाधिकारी पूँजीपति इस तरह के बड़े घोटालों में फँसा खड़ा हो तो यह और भी सुस्पष्ट हो जाता है। वहाँ तो सत्ता के चाहे जो भी चट्टे-बट्टे हों, वे मामले को वहीं रफा-दफा करने की कोशिश में कूद पड़ते हैं। बिजली की चमक की तेजी के साथ सारे आरोप हवा में गायब हो जाते हैं। 2जी घोटाले में कुमार मंगलम और राडिया टेप घोटाले में टाटा का नाम उभर कर आना ऐसे ही दो सुस्पष्ट उदाहरण हैं।

महत्वपूर्ण होने के बावजूद सरकार और राजनीतिज्ञ राजसत्ता के अस्थाई सदस्य होते हैं। इसके स्थाई स्तम्भ भ्रष्टाचार के संदर्भ में कोई उजली तस्वीर पेश नहीं करते हैं। हालाँकि जनता का मानना है कि पुलिस सबसे अधिक भ्रष्ट और पूँजीवादी समाज की सबसे संगठित गुण्डा वाहिनी है। वे संभवत: सोचते हैं कि मिलिट्री जिसपर मातृभूमि की रक्षा का जिम्मा है वह अनुशासित और ईमानदार होती है। उनके इस विश्वास को तोड़ते हुए, एक सेना प्रमुख ने एक टीवी साक्षात्कार में खुलासा किया कि उन्हें एक लेफ्टिनेंट जनरल की ओर से घटिया सैनिक वाहन खरीद के एक सौदे को सिरे चढ़ाने के लिए मोटी रकम देने की पेशकश की गई थी जिसका हथियारों और उपकरणों की युद्ध क्षमता और पर्याप्तता पर बहुत बुरा असर पड़ता। फिर लेखा-नियंता एवं महा लेखापरीक्षक (कैग) ने सन 2009 में सेना में अस्पतालों के लिए बहुपयोगी इलैक्ट्रिक वाहनों के रूप में सेना को 1.17 करोड़ रुपए खर्च कर गोल्फ गाड़ियों का अधिग्रहण करते पाया। सन 2013 में भारतीय वायु सेना के लिए होने वाले 12 वीवीआईपी हैलीकॉपटरों के सौदे में भी कैग ने घूस के मामले में एतराज किया था जिसकी कीमत लगभग 3600 करोड़ रुपये थी। यह सौदा अगस्ता वेस्टलैण्ड की इटेलियन-ब्रिटिश फर्म से था जो फिनमेकानिका नामक इटेलियन कम्पनियों के समूह की सहायक कम्पनी थी। राजनैतिक हंगामे की वजह से सरकार को यह सौदा रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालाँकि भ्रष्टाचार का लम्बा हाथ आगे और भी उजागर हो गया जब इस सौदे में एक कथित बिचौलिए ने इटली की अदालत में लिखित में बयान दिया कि इसे हस्तगत करने के लिए यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके करीबी लोगों को 'टारगेट' करने की सलाह अगस्ता वेस्टलैण्ड के उच्च अधिकारियों को दी गई थी। अभी हाल ही में भण्डाफोड़ हुए इण्डियन मिलिट्री एकादमी (आईएमए) भर्ती घोटाले में साजिश, जालसाजी और फर्जी दस्तावेज, फर्जी अनुभव सर्टिफिकेट तैयार करने और अपने चहेते उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा पास करने में मदद करने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं में घालमेल करने के आरोप में अपराधियों की सूची में वहाँ नौकरी करने वाले लेफ्टीनेंट कर्नलों के नाम दर्ज किए गए। अन्य तीन आईएमए कर्मचारियों को सह-अभियुक्त बनाया गया है और इनमें मेजर जनरल सहित और भी कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के संलिप्त होने का शक है। अत: यह दर्शाता है कि अनुशासित फौज कैसे अपने अधिकारियों की भर्ती कर रही है, रक्षा उपकरणों और हथियारों की खरीद कर रही है। फौज में भी भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पर है।

और न्यायपालिका का क्या हाल है जहाँ लोग इन्साफ पाने के लिए गुहार लगाते हैं? जैसा कि जिक्र किया गया, घोटालों के भण्डाफोड़ फिलहाल राजनैतिक वर्ग को झकझोर रहे हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की एक खण्डपीठ निष्कपट भाव से कबूल करती है ''इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाल में कुछ काला है'', और इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ न्यायाधीशों की सन्तानों ने उसी कोर्ट में वकालत करते हुए हैरान कर देने वाले थोड़े से समय में ही बेशुमार धन-दौलत के अम्बार लगा लिए हैं, वह इसकी आलोचना करती है। फिर एक पूर्व कानून मंत्री शान्ति भूषण ने भारत के आठ पूर्व न्यायाधीशों पर ''भ्रष्टाचार'' का आरोप लगाते हुए और उनका नाम लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी थी। एक अभूतपूर्व कदम में भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के. जी. बालाकृष्णन ने कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सौमेन सेन द्वारा स्टील अथोरिटी ऑफ इण्डिया बनाम शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के बीच एक मुकदमे में रिसीवर के तौर पर जो पैसा उन्हें प्राप्त हुआ था, उसे अपनी सुविधानुसार अपने खुद के इस्तेमाल के लिए पैसे में तब्दील कर दिये जाने, साथ ही साथ सम्बन्धित फण्ड का गबन करने के कारण उन्हें पद से हटा देने के लिए एक संवैधानिक मुकदमा शुरू किया था। हालाँकि जस्टिस बालाकृष्णन को खुद भी केरल में एक युवा कांग्रेस के नेता, एक वकील और उनके दामाद की परिसम्पत्तियों की ''चक्कर में डाल देने वाली बढ़ोतरी की खबर की छानबीन करने की कई हलकों से उठी मांग से दोचार होना पड़ा था। इस सम्बन्ध में न्यायपालिका की दुखदायक भूमिका 2002 के खौफनाक गुजरात हत्याकाण्ड की घटना से और भी साफ तौर पर जगजाहिर हुई है जिसे राज्य के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा व्यक्तिगत तौर पर सुनियोजित और गुप्त रूप से अंजाम दिया गया था और निश्चित अल्पावधि तक लगातार उसकी निगरानी की गई थी। धर्मनिरपेक्ष ताकतों के दबाव में सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा था। और 2009 में लम्बे 7 साल के अर्से के बाद, जो अरसा दोषी ठहराने वाले सबूतों को नष्ट करने के लिए काफी था, अपनी नियमित देखरेख में काम करने वाली विशेष जाँच टीम (एसआईटी) नियुक्त की थी फिर भी 2010 में विशेष जाँच टीम की रिपोर्ट ने एक स्टिंग आपरेशन में पर्दाफाश किया था। जबरदस्त रूप से श्री नरेन्द्र मोदी को लपेट लिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे महज ठण्डे बस्ते में डाल दिया। अन्तत: 2012 में, रस्मो-रिवाजी तौर पर विशेष जाँच टीम ने ''मुकदमा चलाने लायक सबूतों'' के अभाव में श्री नरेन्द्र मोदी और अन्यों को अधिकारिक रूप से दोषमुक्त कर दिया। यह घटनाक्रम न्यायपालिका के बारे में क्या बयां करता है इस बारे में लोग अपनी राय खुद बना लें। इसमें केवल यह बात और जोड़ी जा सकती है कि इस विचार से युक्त रिपोर्ट प्रचार में थी कि यह एक ले-देकर हुई सौदेबाजी थी। श्री नरेन्द्र मोदी को अधिकारिक रूप से दोषमुक्त किए जाने से कांग्रेस को संसद में बीजेपी की ओर से होने वाले हमलों से राहत मिल गई जो हमले एक पर एक हुए उन महाघोटालों पर से उस समय पर्दा उठ जाने से होने वाले थे जिनमें यूपीए के मंत्री-नेता लिप्त पाए गए थे।

राज्यसत्ता रूपी तंत्र का एक और स्थाई अंग, अफसरशाही-कार्यपालिका भी व्यक्तिगत फायदों के लिए भ्रष्टाचार को गले लगाने से गुरेज नहीं करती है और न ही किया। सीबीआई 130 राजपत्रित अधिकारियों सहित 170 पब्लिक सर्वेण्टों पर मुकदमा दर्ज करती पाई गई। इनमें से ज्यादातर 116 मुकदमे भ्रष्टाचार निरोधक कानून की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज हुए थे। प्रधानमंत्री तक भी जिसके सदस्य हैं उस पैनल द्वारा की गई केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति पर भी सवाल उठे क्योंकि वे पामोलिन घोटाले या 2जी घोटाले जैसे कोर्ट के मामलों से जुड़े रहे थे। लेकिन जब सीबीआई का बतौर एक तथाकथित स्वतंत्र जाँच बॉडी होने का सवाल आया तो इस पर भी उंगली उठी। हाल ही के एक जीते-जागते उदाहरण में, सीबीआई ने मार्च 2007 में नन्दीग्राम में किए गए निर्मम हत्याकाण्ड और गुण्डागर्दी के लिए सीपीआई(एम) और इसकी सरकार को क्लीन चिट दी थी। लेकिन वर्दीधारी पर चप्पल पहने हुए पुलिस वालों का छद्मावेश धारण किए हुए सीपीआई(एम) के कार्यकर्ताओं द्वारा वहाँ निहत्थे प्रदर्शनकारी किसानों पर गोलियाँ चलाए जाने और बदला लेने की रण हुँकार भरते हुए पीड़ितों का पीछा करने के तथ्य को बेशर्मी से नजरअंदाज कर दिया गया था। यह देश में एक ऐसी घोर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई थी जो इससे पहले कभी सुनने में नहीं आई। इसे मीडिया के एक हिस्से की सराहनीय साहसी भूमिका के सौजन्य से दुनिया ने छोटे पर्दे पर लाइव देखा था। सीबीआई ने इन बातों की साफ तौर पर अनदेखी कर दी थी। अगर श्री नरेन्द्र मोदी को अधिकारिक रूप से दोषमुक्त कर देना सर्वोच्च न्यायालय की देन था तो नन्दीग्राम नरसंहार पर सीबीआई की इस ताजातरीन रिपोर्ट ने साफ तौर पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई इस टिप्पणी को सही ठहरा दिया कि सीबीआई केन्द्र सरकार का तोता है। आगामी लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के लिए बहुत अनुकूल नहीं, ऐसे कुत्सित गठबन्धनों और घटनाक्रमों के बीच में, सीपीआई(एम) के साथ अपनी पुराने जमाने की दोस्ती को तरोताजा करने की नई सम्भावनाओं का

(शेष पृष्ठ 7 पर)

संगठन व आन्दोलन को मजबूत बनाने के संकल्प के साथ
आशा वर्कर्स सम्मेलन सम्पन्न

दिल्ली : अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के प्रेरणादायक संघर्ष की सीख को ग्रहण करते हुए दिल्ली आशा वर्कर्स एसोसिएशन ने अपना पहला सम्मेलन 7 मार्च को आदर्शनगर में आयोजित किया जिसमें सैकड़ों आशा वर्करों ने भाग लिया। सम्मेलन में 8 मार्च अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संग्रामी इतिहास के बारे में बताया गया।

एसोसिएशन की महासचिव ममता राव ने सम्मेलन में अपनी सांगठनिक रिपोर्ट की। एसोसिएशन के अध्यक्ष दिल्ली एआईयूटीयूसी के सचिव कॉ. मैनेजर चौरसिया ने भी सम्मेलन को सम्बोधित किया। आशा वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी माना जाने और पूर्ण वेतन देने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा कि मणिपुर की सरकार आशा वर्कर को 3000 रुपये प्रतिमाह देती है। कुछ राज्यों में यात्रा व फोन के लिए भी सुविधा दी जाती है। मगर दिल्ली देश की राजधानी है यहाँ कुछ नहीं दिया जाता। उन्होंने 15 सूत्री मांगपत्र पर आन्दोलन तेज करने का आह्वान किया। इस कड़ी में मई में एक कार्यशाला व जुलाई में एक राज्य स्तरीय प्रदर्शन करने की उन्होंने घोषणा की।

सम्मेलन को एआईयूटीयूसी के राष्ट्रीय सचिव मण्डल के सदस्य कॉ. आर.के. शर्मा ने अपने सम्बोधन में संगठन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने संगठन व आन्दोलन को तेज व मजबूत बनाने का आह्वान किया।

इस सम्मेलन को एआईयूटीयूसी के दिल्ली राज्य अध्यक्ष हरीश त्यागी, आंगनबाड़ी वर्कर्स व हैल्पर्स एसोसिएशन के सलाहकार कॉ. रामकरण, आशा वर्कर राजबाला, कविता, बबीता, आशा, सीमा, निर्मला आदि ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम का संचालन कविता द्वारा किया गया। इस सम्मेलन को हरियाणा आशा वर्कर्स यूनियन की ओर से सुषमा ने सम्बोधित किया।

आंगनबाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स एसोसिएशन, दिल्ली का शानदार सम्मेलन

दिल्ली: आंगनबाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स एसोसिएशन दिल्ली की तरफ से 5.3.2014 को बवाना की चौपाल में सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें दिल्ली के विभिन्न क्षेत्र से प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया 300 से अधिक आंगनबाड़ी वर्करों व हैल्परों को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं एवं सहायिका यूनियन हरियाणा की महामंत्री श्रमति पुष्पा दलाल केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठन एआईयूटीयूसी के प्रदेश अध्यक्ष हरीश त्यागी एवं आंगनबाड़ी वर्कर्स एसोसिएशन के सलाहकार रामकरन ने सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार आंगनबाड़ियों को अब कार्पोरेट घरानों के सुपुर्द करने की नापाक साजिश रच रही है। इससे सरकार आईसीडीएस की असल योजना को ही ध्वस्त करने व अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। सरकार का यह कदम कुपोषित बच्चों व माताओं को गर्त में धकेल देगा। वक्ताओं ने यह भी कहा कि सरकार आंगनबाड़ी कर्मियों से विभिन्न योजनाओं व सर्वे आदि के लिए काम तो ले रही है मगर उन्हें इसके बदले मेहनताना नहीं दे रही है। जबकि आंगनबाड़ी कर्मियों को सरकारी कर्मचारी माना जाना चाहिए एवं उन्हें पूर्ण वेतन व सभी सेवा हितलाभ दिए जाने चाहिएं। इस सम्मेलन में नई कमेटी का गठन किया जिसमें श्री रामकरन को सलाहकार, मैनेजर चौरसिया को अध्यक्ष व श्रमवन्ती को महासचिव तथा निर्मला, आरती, मधु, सविता, गीता शर्मा सहित 25 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। इस सभा में अल्का, सत्यवती, गीता, दर्शना ने भी अपने विचार रखे। सभा का समापन कॉ. मैनेजर चौरसिया ने संगठन को मजबूत बनाने की अपील के साथ उत्साहवर्धक माहौल में किया।

सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कॉ. मैनेजर चौरसिया

जंतर मंतर पर बिजली कर्मियों व इंजीनियरों का धरना

दिल्ली : बिजली कर्मियों और इंजीनियरों की नेशनल कॉआर्डिनेशन कमेटी की ओर से 21 फरवरी को यहां जंतर मंतर पर धरना दिया गया। लोग वहन कर सकें ऐसे रेट पर बिजली प्रदान करने के लिए बिजली बिल 2003 की पुनः समीक्षा करने, निजी बिजली वितरण कम्पनियों की लूट में मददगार बनाने के लिए कानून में प्रस्तावित संशोधन रद्द करने, अनबंडलिंग, निजीकरण, फ्रेंचाइजीकरण बंद करने, प्राइवेट लाइसेंस/फ्रेंचाइजी रद्द करने, जनहित में सार्वजनिक क्षेत्र में बिजली उत्पादन, संचारण और वितरण को समन्वित करने, निजी वितरण कम्पनियों के हिसाब खाते का कैग द्वारा लेखा परीक्षण सुनिश्चित करने और आउटसोर्सिंग, ठेका प्रथा खत्म करने, जब तक ठेका श्रमिकों की सेवाएं नियमित नहीं हो जाती तब तक उन्हें न्यूनतम बेसिक पे देना सुनिश्चित करने की मांग की गई।

धरने को ऑल इण्डिया इंजीनियर्स फेडरेशन के महासचिव इंजीनियर शैलेन्द्र दुबे, डीवीबी इंजीनियर्स एसोसियेशन के महासचिव इंजीनियर सत्यपाल, इइएफआई के महासचिव पीएन चौधरी, ऑल इण्डिया पावरमैन फैडरेशन के कॉमरेड आर के शर्मा व अन्य वक्ताओं ने सम्बोधित किया। धरने में सैकड़ों बिजली कर्मियों ने शिरकत की।

भवन निर्माण श्रमिकों के धरने प्रदर्शन

झज्जर में कारीगर-मजदूरों को सम्बोधित करते हुए कॉ. सत्यवान

रोहतक (हरियाणा): एआईयूटीयूसी से सम्बद्धित भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन ने अपनी ज्वलंत मांगो को लेकर मुख्यमंत्री के नाम रोहतक के उपायुक्त के नम एक ज्ञापन दिया। जिला भर से मजदूर व कारीगर पहले मानसरोवर पार्क में इकट्ठा हुए। वहाँ से जुलूस के रूप में वे लघु सचिवालय पहुँचे। यूनियन के जिला सचिव कॉ. जगदीश चन्द्र व अन्य यूनियन नेताओं ने मजदूरों से सजग रहने और किसी के भी झांसों में न आने की अपील की। यूनियन नेताओं ने मजदूर कल्याण मंच बहादुरगढ़ के नेता जयकरण माण्डौठी को एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) द्वारा रोहतक लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित करने पर अपार खुशी प्रकट की और एक स्वर से निर्णय लिया कि जिला के मजदूर-कारीगर उन्हें भरपूर समर्थन देंगे और उनके पक्ष में जनमत बनाएंगे। मजदूरों को यूनियन के प्रदेश महासचिव बलराम यादव, श्रमिक किसान नेता कॉ. जयकरण माण्डोठी व ऑल इण्डिया यूटीयूसी के प्रदेश अध्यक्ष कॉ. सत्यवान के अलावा, राजकुमार काठमण्डी, धर्मबीर भिवानी, राजकुमार जांगड़ा आदि नेताओं ने भी सम्बोधित किया।

रोहतक में कारीगर-मजदूरों को सम्बोधित करते हुए कॉ. जयकरण माण्डोठी

भिवानी में 20 फरवरी को कारीगर-मजदूरों को सम्बोधित करते हुए कॉ. धर्मबीर सिंह

8 मार्च....

(पृष्ठ 2 का शेष)

कार्यक्रम शुरू हुआ। इस घटना की सभी सम्मानित नागरिकों ने कड़े शब्दों में निन्दा की। आन्दोलन को आगे बढ़ाते हुए अब मुरादाबाद लोकसभा के संभावित प्रत्याशियों के नाम ''खुला पत्र'' जारी कर नीरज भड़ाना हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे जाएंगे।

वसुंधरा, गा.बाद (यूपी): 8 मार्च को महिला सांस्कृतिक संगठन के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केशव पार्क सेक्टर 17 में मनाया गया।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में संगठन की दिल्ली राज्य सचिव रितु कौशिक ने उपस्थित जनता को सम्बोधित करते हुए कहा कि समाज में आज जो महिलाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं उसके लिए महिलाओं को हर स्तर पर एक जबरदस्त आन्दोलन छेड़ना होगा। इस आन्दोलन में सरकार पर महिला सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने, कानूनों को सख्ती से पालन करने, महिला पुलिस की संख्या बढ़ाने पर जोर देना होगा। आन्दोलन के माध्यम से मनोरंजन के माध्यमों में महिलाओं को एक उपभोग की वस्तु के रूप में दिखाने, इण्टरनेट पोर्नोग्राफी, टीवी पर अश्लील प्रसारण पर रोक लगाने का दबाव डालना होगा।

कार्यक्रम की संयोजिका आकांक्षा भारद्वाज ने भी सम्बोधित किया।

'अनपढ़ बहू' नामक नाटक का मंचन किया गया। कार्यक्रम का संचालन आकांक्षा भारद्वाज, नीरज कुशवाहा, मोना पन्त और प्रीति ने किया।

महाराष्ट्र के विदर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया

नागपुर: 8 मार्च अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एआईएमएसएस की नागपुर जिला शाखा की ओर से दोपाहर 1 बजे ''राष्ट्रभाषा प्रचार समीति'' बर्डी में जाहिर सभा का आयोजन किया गया था। सभा की अध्यक्षा संगठन की जिला सचिव संगीता पंवार ने अपने भाषण में कहा कि पूरे समाज में महिलाओं की संख्या आधी है। हम सही उद्देश्य व दिशा में संगठित नहीं होने से पिछड़ी हुई हैं।

सभा की मुख्य वक्ता एआईएमसएस की जिला अध्यक्षा कॉ. नन्दिनी भोण्डे ने कहा कि 8 मार्च अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उद्देश्य अंधश्रद्धा, कुसंस्कार व सभी क्षेत्रों में स्त्री-पुरुष समानता के आधार पर संघर्ष करके शोषणमुक्त समाज बनाना है। उसे पूरा करने के लिए संगठित होना आवश्यक है। प्रमुख अतिथि अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की महाराष्ट्र महिला संगठिका छाया सावरकर थी। मोहगाव झिल्पी की उपसंरपंच वंदना रंदई, गंगूबाई डोईफोडे, मालतीबाई, डाखले, बेबी भोपे, प्रिती खोटे ने भी विचार रखे। सभा में कुसुम शंभरकर ने महिला अत्याचार व सावित्रीबाई फूले पर रचित गीत गाए। सभा का संचालन ज्योति ठाकरे ने किया। सभा में नन्दिनी भोण्डे व उपसरपंच बंदना रंदई ने दो प्रस्ताव पेश किए। वे इस तरह थे: 1. महाराष्ट्र में फिलहाल हुई ओलावृष्टि से प्रभावित किसान-खेतमजदूरों को तुरन्त उचित मुआवजा दिया जाए। इसमें लोकसभा चुनाव का बहाना न लिया जाए। 2. तालुका स्तर पर महिला अधिकारियों की तुरन्त नियुक्ति की जाए।

सभा में मोहगांव झिल्पी, किन्हीं धनोली, वानाडोंगरी, वाडी व शहर की महिला-पुरुष कार्यकर्ता शामिल थे।

मध्य प्रदेश में विचार गोष्ठी का आयोजन

सागर : अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में गत दिवस तहसील परिसर सागर में ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन सागर इकाई द्वारा एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। ए.आई.एम.एस.एस. की राज्य संयोजक रचना अग्रवाल ने वर्तमान समाज में महिला भ्रूण-हत्या, दहेज हत्या व आत्महत्या, यौन शोषण व उत्पीड़न, दुष्कर्म व सामूहिक दुष्कर्म जैसी इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं को आजादी के 66 वर्ष गुजर जाने के बावजूद आज भी जनतांत्रिक मूल्यबोध यानी पुरुष-स्त्री समानता का हक हासिल नहीं हुआ है, उसे अबला समझा जाता है तथा सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता। टी.वी., फिल्मों, इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया, सौंदर्य प्रतियोगिताओं तथा विज्ञापनों में ''माल'' की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे समाज का अधिकांश हिस्सा महिलाओं को उपभोग की वस्तु से अधिक नहीं मान रहा है। फलत: पाश्विक घटनाएं दिनो दिन बढ़ती जा रही हैं। भोपाल जिला प्रभारी जॉली सरकार ने सही वैज्ञानिक समझदारी अपनाने की जरूरत पर बल दिया। जिज्ञासा मिश्रा ने देश के पूर्वोत्तर की महिलाओं के संघर्ष को याद करते हुये कहा कि हमें समाज में बेहतर मूल्यबोधों की स्थापना के लिये सतत् संघर्ष करना होगा। कार्यक्रम का आगाज और अंत सोना कुशवाहा द्वारा प्रस्तुत जनतांत्रिक गीतों से किया गया। संचालन पूजा चौरसिया ने किया। गोष्ठी में गुना जिला अध्यक्ष संगीता आर.बी, सरिता पटैल, भारती अहिरवार, मंजू पटेल, मनीषा गौंड़, सपना व मंजू अहिरवार सहित अनेक छात्राएं तथा महिलायें मौजूद थी।

हरियाणा में महिला सम्मेलन

रेवाड़ी : यहां महिला सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें मुख्य वक्ता थी एआईएमएसएस की अखिल भारतीय अध्यक्ष श्रीमती छाया मुखर्जी। रितु कौशिक भी मौजूद थी।

महिलाओं ने निकाला राजभवन पर जुलूस

झारखण्ड (राँची): राँची के चुटिया स्थित ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की होस्टल वार्डन सुचित्रा मिश्रा उर्फ माला मिश्रा हत्याकाण्ड की जाँच कराने, सुचित्रा मिश्रा को पूर्ण न्याय दिलाने और झारखण्ड में महिलाओं पर दिन-प्रतिदिन बढ़ते अपराध को रोकने की मांग को लेकर ऑल इण्डिया एमएसएस की राँची जिला कमेटी की ओर से 1 मार्च को सैकड़ों महिलाओं ने जयपाल सिंह स्टेडियम से राजभवन तक एक जुलूस निकाला और ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल उस दिन मौजूद नहीं थे, इसलिए अगले दिन ऑल इण्डिया एमएसएस के एक प्रतिनिधिमण्डल को उन्होंने मिलने के लिए बुलाया। उनके समक्ष प्रतिनिधिमण्डल ने इस हत्याकाण्ड की सही जाँच सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया। इसके अलावा प्रतिनिधिमण्डल ने कहा कि पुलिस प्रशासन सुचित्रा मिश्रा के गरीब और निर्दोष परिवार वालों के साथ अभद्र व्यवहार कर रही है एवं मानसिक प्रताड़ना दे रही है। यहाँ तक कि परिवार बर्बाद करने की धमकी दे रही है, विशेषकर काँके थाना प्रभारी। संगठन ने पुलिस पर उचित कार्रवाई करने को भी आग्रह किया।

राज्यपाल की ओर से उपर्युक्त मांगों पर उचित कार्रवाई का आदेश दिए जाने का आश्वासन भी दिया गया। प्रतिनिधिमण्डल में कॉ. केया डे, संध्या पाण्डे, बिमला देवी, अशोका मण्डल, सीमा व ललिता शामिल थी।

दुर्ग (छ.ग.) में साइकिल रैली

27 फरवरी को शहीद चन्द्रशेखर आजाद दिवस पर साइकिल रैली निकाली गई। 'आजादी आन्दोलन के क्रान्तिकारी शहीदों के जीवन-संघर्ष को इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में शामिल करो' की मांग पट्टिकाओं से सुसज्जित साइकिल रैली ने शहर की परिक्रमा की। रैली के बाद हुई सभा को डीएसओ संयोजक कॉ. आत्माराम साहू ने बात रखी। सभा का संचालन नीतू साहू ने किया।

जीएसवीएम, कानपुर के मेडिकल छात्रों पर हुए बर्बर हमले का एआईडीएसओ ने किया प्रतिवाद

जीएसवीएम, कानपुर के मेडिकल छात्रों पर हुए बर्बर हमले का प्रतिवाद करते हुए एआईडीएसओ की ओर से यह ब्यान जारी किया गया :

एकबार फिर मेडिकल छात्र शासक पार्टी द्वारा समर्थित गुण्डागर्दी का शिकार हुए हैं। इस बार जीएसवीएम, कानपुर के मेडिकल छात्रों और जूनियर डाक्टरों पर समाजवादी पार्टी के एमएलए मिस्टर इरफान सोलंकी और उसके गुण्डों द्वारा बर्बर हमला किया गया। 28 फरवरी को उन्होंने छात्रों पर गालीबारी की और अनेक को घायल कर दिया। पुलिस ने एमएलए और गुण्डा तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाए 24 मेडिकल छात्रों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए। हम इस बर्बर हमले और पुलिस प्रशासन की घृणित भूमिका की तीव्र निन्दा करते हैं। स्वाभाविक ही है कि जीएसवीएम के छात्रों और उत्तर प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने इस हमले के खिलाफ आन्दोलन शुरू कर दिया। जीएसवीएम के छात्रों तथा अन्य राज्यों के मेडिकल छात्रों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के मेडिकल छात्रों के इस आन्दोलन का हम भरपूर समर्थन करते हैं। यह एक दस्तूर बन गया है कि सीधे शासक पार्टी या शासक पार्टी का छात्र संगठन बाहरी असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर देश में सभी जगह मेडिकल छात्रों, डॉक्टरों, नर्सों पर हमले कर रहे हैं। कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, सीपीआई(एम), तृणमूल कांग्रेस इत्यादि जैसी संसदीय पार्टियाँ शैक्षणिक संस्थानों में और खास तौर पर मेडिकल कॉलेजों में हिंसा फैला रही हैं। गौरतलब है कि उन मेडिकल छात्रों की सुरक्षा को कोई इंजताम नहीं है जो शासक पार्टी तथा उसकी जनविरोधी स्वास्थ्य नीतियों और शिक्षा-विरोधी नीतियों का विरोध करते हैं। एआईडीएसओ लम्बे अर्से से भारी फीस वृद्धि और शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र के निजीकरण-व्यापारीकरण के खिलाफ छात्र आन्दोलन गठित कर रहा है। हम आमतौर पर शिक्षण संस्थानों और विशेषकर मेडिकल कॉलेजों और हस्पतालों में पर्याप्त ढांचागत सुविधाओं, उचित अध्यापक-छात्र अनुपात और जनमुखी स्वास्थ्य नीति की मांग कर रहे हैं। छात्रों-अध्यापकों और नॉन-टीचिंग स्टाफ की सुरक्षा की मांग को लेकर भी हम छात्र आन्दोलन गठित कर रहे हैं। शिक्षा पर हो रहे तमाम हमलों के खिलाफ मेडिकल सांईस की नैतिकता को बुलन्द रखते हुए एआईडीएसओ इन आन्दोलनों को संचालित कर रहा है।

कानपुर में मेडिकल छात्रों पर हुए इस बर्बर हमले के खिलाफ एआईडीएसओ ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किए। एआईडीएसओ ने प्रतिवाद जुलूस, कैण्डल मार्च और मेडिकल कॉलेजों और देश के महत्वपूर्ण शहरों में काले बिल्ले लगाने के कार्यक्रम लिए हैं और छात्रों से आन्दोलन को मजबूत करने की अपील की।

एआईडीएसओ की मांग है कि 1. कानपुर के मेडिकल छात्रों पर हमले के आरोपी एमएलए और गुण्डा तत्वों को तुरन्त गिरफ्तार किया जाए और उदाहरणमूलक सजा दी जाए। 2. जीएसबीएम कानपुर के छात्रों के ख्विालाफ दर्ज झूठे केस तुरन्त वापस लिए जाएं। 3. तमाम घायल छात्रों को मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाए। 4. जीएसवीएम और अन्य मेडिकल कॉलेजों के छात्रों और टीचरों के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

कार्ल मार्क्स स्मृति दिवस पर विचार गोष्ठी

सागर (म.प्र.) : सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) जिला संगठन समिति सागर के तत्वावधान में 14 मार्च को चेतना अध्ययन केंद्र यादव कालोनी में क्रांतिकारी विज्ञान, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के प्रणेता व वैज्ञानिक समाजवाद एवं साम्यवाद के जनक महान क्रांतिकारी कार्ल मार्क्स के 131वें स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया।

विचार गोष्ठी के मुख्य वक्ता पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड रामावतार शर्मा ने मार्क्सके जीवन-संघर्ष व मार्क्सवाद के विभिल्न पहलुओं पर चर्चा की।ें सर्वहारा वर्ग को वे जिंदगी भर संगठित करते रहे और जिसके हाथ में उन्होंने एक अजेय हथियार, द्वन्द्वात्मक वस्तुवाद दिया। विचार गोष्ठी के अन्य वक्ता प्रोफेसर डी.सी. शर्मा ने भी अपनी बात रखी। गोष्ठी में राजू पटेल, गणेश पटेल, संजय तिवारी, सोना कुशवाहा, जिज्ञासा मिश्रा आदि उपस्थित थे। गोष्ठी का संचालन अशोक कुशवाहा ने किया ।

कॉमरेड शिवलाल प्रसाद लाल सलाम

सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) की बिहार राज्य कमेटी के सदस्य-सह-कार्यालय सचिव और ऑल इण्डिया यूटीयूसी के बिहार राज्य उपाध्यक्ष कॉमरेड शिवलाल प्रसाद का गत 10 मार्च को देहांत हो गया।

कॉमरेड शिवलाल प्रसाद

लाल सलाम!

भ्रष्टाचार.....

(पृष्ठ 4 का शेष)

प्रकट होना आंका गया हो सकता है! क्या भ्रष्टाचार का मतलब पैसे के दुरुपयोग में संलिप्त होना ही होता है? क्या ये गन्दे राजनैतिक खेल खेदजनक भ्रष्ट करतूत होने का खिताब पाने लायक नहीं हैं?

लोकतांत्रिक राज्य का चौथा खम्बा, मीडिया को लोकतंत्र का प्रहरी कहा जाता है। हालांकि पैसे या सुविधाओं के ऐवज में खबरें छापने के आरोप कोई कम और विरले ही नहीं हैं। इसके अलावा, बढ़ते घोटालों के रूबरू स्टिंग असपरेशन नामक तरीका पर्दे के पीछे या गुप-चुप होने वाले सौदों का साहस के साथ रहस्योद्घाटन करने के लिए लोकप्रिय हुआ। बदकिस्मती से अग्रणी मीडिया पर्सन और ऐसे स्टिंग आपरेशनों की मिसाल पेश करने वाले अनुचित फायदा उठाने और अपनी महिला इन्टर्नों से छेड़छाड़ करने के आरोपों से रूबरू हैं। साफ जाहिर है कि मीडिया भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस लड़ाई छेड़ने की अक्सर डींग हांकता है ऐसा रहस्योद्घाटन उस लड़ाई में निश्चित नुकसानदेह भूमिका अदा करता है।

उपरोक्त वर्णन भारत में भ्रष्टाचार के इन्द्रधनुष का एक अंश ही है। यह समस्या की घनघोरता का शायद ही कोई प्रतिनिधित्व करता है। यह निश्चित ही एक अनिष्टकारी प्रभाव डालता है। शासक वर्ग, उद्योगपति-एकाधिकारी पूंजीपतियों के साथ ही भारतीय पूंजीवादी राज्य के राजसत्ता रूपी तंत्र के ये सब स्थाई स्तम्भ यानी कार्यपालिका-अफसरशाही-फौज-न्यायपालिका और सरकार जैसे अस्थाई राजनैतिक प्रबन्धक पर्याप्त रूप से भ्रष्टाचार के खिताब से नवाजे जाते हैं। भ्रष्टाचार सबसे ऊपरी स्तरों से शुरू होता है और आहिस्ता-आहिस्ता रिसकर नीचे की तरफ आता है।

इसलिए संसदीय चुनाव की पूर्व संध्या पर राजनैतिक पार्टियों द्वारा भ्रष्टाचार पर मचाया जा रहा मौजूदा शोर असली मुद्दों से लगों को ध्यान दूसरी तरफ फेर देने की चाल के सिवाए और कुछ नहीं है। यही वे राजनैतिक पार्टियाँ हैं जो भ्रष्टाचार मचा रही हैं, अब इसके खिलाफ शोर मचाती हुई जहर उगल रही हैं। साथ ही वे इस सच्चाई पर पर्दा डाल देती है कि यह समूची पूँजीवादी व्यवस्था ही–इसकी इस मरणासन्न अवस्था में पूँजीवादी राजसत्ता के सभी अंग ही हर पल, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार को पनपा रहे हैं। मुनाफा कमाने पर फलने-फूलने वाला पूँजीवाद शोषण की ओर ले जाता है; शोषण गरीबी, बेरोजगारी, अनपढ़ता और साथ ही साथ आक्रोश और असंतोष को पनपाता है। जनआक्रोश को दबाने के लिए दमन ही शासकों का आखिरी सहारा है। हालाँकि, सामाजिक द्वन्द्व के अटल नियमों पर चलते हुए, शोषण संकट पैदा करता है; बाजार संकट मुनाफा कमाने पर ब्रेक लगा देता है लेकिन येन-केन-प्रकारेण अधिकतम मुनाफा हड़पने की आग को भड़का देता है। इसलिए पूँजीवाद न केवल बेरहमी से लोगों के खून का आखरी कतरा तक निचोड़ लेता है, बल्कि यह इसके द्वारा सृजित मूल्यबोंधों को भी अब यह चकनाचूर कर देता है और पैरों तले रौंद देता है। यह लोगों को अपने देश के भौतिक, आर्थिक और मानव संसाधनों तथा न जाने और किस-किस की कीमत पर भी येन-केन-प्रकारेण धन के अकूत अम्बार लगाने देता है। इस प्रकार भ्रष्टाचार आग में घी डालने का काम करता है। एक समय था जब इसे नफरत की निगाह से देखा जाता था, अब यह पूँजीवादी शोषण का, इस शोषणमूलक पूँजीवादी समाज का एक अभिन्न अंग बन गया है।

ऐसी स्थिति में चुनाव से और गार्ड बदल देने से लोगों को भ्रष्टाचार से निजात नहीं मिल सकती है। दागी भ्रष्ट लोगों को कानून बनाने वाली बॉडियों में घुसने से रोक कर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के कुछ लोगों द्वारा सुझाए टोटकों से भी भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं है। बल्कि इन बुर्जुआ पार्टियों और नेताओं में से चाहे जो कोई भी सत्ता में आए, अपने आका शासक एकाधिकारी पूँजीपतियों की ताबेदारी में खुद को लगभग हमेशा ही लगाए रखेगा, वह महज खुद को और अपने संगी-साथियों को भी येन-केन-प्रकारेण अपनी धन-दौलत के अकूत अम्बार लगाने देने के कदम उठाएगा और नीतियाँ बनाएगा तथा अपनी सत्ता और धन के पीछे ही दौड़ता रहेगा।

पूँजीवाद की तमाम व्याधियों की तरह जीवन की इस गन्दगी, भ्रष्टाचार को मिटाने का एकमात्र रास्ता पूँजीवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने और मार्क्सवाद-लेनिनवाद की नई जीवन्त व उत्साहपूर्ण विचारधारा और संस्कृति की नींव पर निर्मित एक नया गतिशील समाजवादी समाज कायम करने में ही निहित है। लेकिन इसके साथ ही, पूँजीवाद इसकी भ्रष्टाचार की बाढ़ के साथ-साथ इसकी विपरीतता के तौर पर जनाक्रोश और जनरोष को भी जन्म देता है, यह शोषित-पीड़ित लोगों के तमाम तबकों को समाहित करते हुए लोगों को जिन्दगी और रोजी-रोटी की तमाम ज्वलन्त समस्याओं को लेकर उच्चतर आदर्श-संस्कृति-नीति नैतिकता पर आधारित जनआन्दोलनों और वर्ग संघर्षों को भी पैदा करता है।

अत: इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का अन्तिम लक्ष्य जब तक हासिल नहीं हो जाता तब तक झाड़ू से या किसी और तरीके से भ्रष्टाचार दूर करने के किसी झूठे झांसे में न आकर, भ्रष्टाचार मचाने वाले किसी भी शख्स को न बख्शते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों का जोरदार जनआन्दोलन गठित करने के लिए अपनी मजबूत और संगठित आवाज बुलन्द करनी होगी। केवल एक यथार्थ जनपक्षीय सही नेतृत्व में दुर्जेय बनाए गए ऐसे जनआन्दोलन ही भ्रष्टाचार की तेजी से बढ़ती बाढ़ को रोकने के एक प्रमुख जरिये के तौर पर काम कर सकते हैं।

लोग इस सच्चाई को गहराई से समझने और इस प्रक्रिया को तेज करने के इस संघर्ष में शामिल होने के काम के रूबरू हैं। यह काम मानवीय, भौतिक, भावनात्मक, आर्थिक और मानव सम्बन्धी हर तरह के संसाधनों के कम से कम नुकसान सहित जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर है।

केरल में .....

(पृष्ठ 1 का शेष)

स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तीन घटक पार्टियों के कार्यकर्ताओं के अलावा भारी संख्या में जनता ने भी उत्साहपूर्वक सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन की अध्यक्षता एसयूसीआई(सी) के केन्द्रीय कमेटी सदस्य और केरल राज्य सचिव कॉमरेड सी.के. लुकोस तथा उद्घाटन आरएमपी की राज्य सचिवमण्डल सदस्य और कत्ल किये गये नेता कॉमरेड टीपी चन्द्रशेखरन की विधवा कॉमरेड केके रीमा द्वारा किया गया। एमसीपीआई(यू) के पोलिट ब्यूरो सदस्य और राज्य सचिव कॉमरेड एम राजन द्वारा एलयूएफ का संयुक्त घोषणा पत्र पेश किया गया।

एसयूसीआई(सी) के राज्य सचिव मण्डल सदस्य और एलयूफ के संयोजक कॉमरेड वी. वेणुगोपाल ने स्वागत भाषण दिया और एसयूसीआई(सी) के राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड एस सीतीलाल ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। तीनों पार्टियों के राज्य नेताओं सहित कॉमरेड टी एल संतोष, एन. वेणु, के. एस. सदानन्दन तथा कोल्लम सीट से एलयूएफ समर्थित आजाद उम्मीदवार श्री के भास्करन ने भी सम्मेलन को सम्बोधित किया।

सम्मेलन द्वारा सर्वसम्मति से गृहीत घोषणा पत्र में भूमण्डलीकरण की नीतियों, साम्प्रदायिकता, भ्रष्टाचार और हिंसा की राजनीति के खिलाफ लोगों के संयुक्त जनवादी आन्दोलन संगठित करने के लिए, राज्य के तमाम वाम और जनवादी सोच रखने वाले लोगों से एलयूएफ के पीछे लामबंद होने का आह्वान किया गया यह भी नोट किया गया कि भूमण्डलीकरण की नीति जो एकाधिकारी पूँजीपतियों की स्वार्थ रक्षा की मास्टर प्लान के सिवाए और कुछ नहीं है को लागू करते हुए सत्ता की भागीदार पार्टियों द्वारा भ्रष्टाचार को संस्थानीकृत कर दिया गया है। कोई भी पार्टी या शक्ति जो भ्रष्टाचार से लड़ना चाहती है उसे इन नीतियों के खिलाफ भी लड़ना चाहिए। वरना वे भी न केवल भ्रष्टाचार खत्म करने में नाकाम रहेंगी बल्कि खुद भी पतित हो जाएंगी।

जब व्यापक मेहनतकश जनता केन्द्र और राज्य सरकारों की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष में बेताबी से नेतृत्व की तलाश कर रही हैं और जब सीपीआई(एम)-नीत लेफ्ट डैमोक्रेटिक फ्रण्ट ने आन्दोलन का रास्ता छोड़ दिया है और शासन तन्त्र का अभिन्न हिस्सा बन गया है। ऐसे एक मोड़ पर एलयूएफ के गठन के ऐतिहासिक महत्व को समझने का आग्रह सभी वक्ताओं ने सभा में उपस्थित लोगों से किया।

सम्मेलन के सफल समापन के बाद शहर में एक जोशपूर्ण जुलूस निकाला गया। एलयूएफ के गठन ने वाम बुद्धिजीवी दायरों और व्यापक जनता में भारी उत्साह और उम्मीदों का संचार किया है।

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2012-2014
Posting at IPMBC on 7–8 and 22–23 Fortnightly, Date of Printing : 20 March, 2014

जन आन्दोलन मजबूत करने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में
एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) उम्मीदवारों को विजयी बनायें

क्र.सं.	राज्य	संसदीय क्षेत्र	उम्मीदवार
1.	आन्ध्र प्रदेश	सिकन्दराबाद	च. मुराहारी
		अनन्तपुर	जी. ललिता
2.	असम	करीमगंज(एससी)	प्रभाष सरकार
		सिलचर	अरुणांग्सु भट्टाचार्य
		धुबड़ी	सूरतज़मान मण्डल
		बरपेटा	खुर्शीदा अनवर बेगम
		मंगलदोई	स्वर्णलता चालिहा
		लखीमपुर	हेमकांन्त मिरी
3.	बिहार	मुज़फ्फरपुर	अशोक कुमार सिंह
		वैशाली	इन्द्रदेव राय
		बांका	दीपक कुमार
		मुंगेर	प्रमोद कुमार
4.	छत्तीसगढ़	दुर्ग	आत्माराम साहू
5.	दिल्ली	उत्तर-पूर्वी दिल्ली	प्रो. नरेन्द्र शर्मा
6.	गुजरात	वडोदरा	तपनदास गुप्ता
7.	हरियाणा	सोनीपत	हरिप्रकाश
		रोहतक	जयकरण माण्डोठी
8.	झारखण्ड	राँची	रामलाल महतो
		जमशेदपुर	सीताराम टुडू
9.	कर्नाटक	गुलबर्गा(एससी)	एस एम शर्मा
		रायचुर (एसटी)	के सोमशेखर
		बैल्लारी (एसटी)	ए देवदास
		धारवाड़	गंगाधर बादीगर
		केन्द्रीय बैंगलोर	ज़ाहिदा शिरीन
		दक्षिण बैंगलोर	एम उमादेवी
10.	केरल	कोट्टयम	एन के बिजू
		अलापुड़ा	एडवोकेट एम ए बिन्दु
		मेवलिक्कारा(एससी)	के एस शशिकला
		पत्तनमथिट्टा	एस राधामणी
		कोल्लम	के भास्करन
		तिरूवनन्तपुरम	एम शजरखान
11.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	सुनील गोपाल
		भोपाल	जे सी बरई
12.	उड़ीसा	सुन्दरगढ़(एसटी)	जस्टिन लुगून
		सम्बलपुर	प्रसादी प्रधान
		जाजपुर(एससी)	सुभाष चन्द्र मल्लिक
		ढेनकनाल	मानसी स्वाई
		कटक	वीणापाणि दास
13.	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	विजय पाल सिंह
		प्रतापगढ़	शेषनाथ तिवारी
		जौनपुर	रविशंकर मौर्य
14.	तमिलनाडू	उत्तरी चेन्नई	वी. शिवकुमार
		दक्षिणी चेन्नई	एस. गणेशन
		तेनी	एम जे वॉल्टेयर
15.	त्रिपुरा	पश्चिमी त्रिपुरा	अरुण भौमिक
16.	पशिचम बंगाल	कूचबिहार(एससी)	नृपेण कार्जी
		अलीपुरदुआर (एसटी)	सुभाष बराईक
		जलपाईगुड़ी (एससी)	हरिभक्त सरदार
		दार्जीलिंग	गौतम भट्टाचार्य
		रायगंज	दुलाल राजबंशी
		बालूरघाट	नुर-उल-ईस्लाम
		उत्तर मालदा	गौतम सरकार
		जंगीपुर	अब्दुस सईद
		मुर्शिदाबाद	बकुल खण्डाकर
		कृष्णानगर	कमल दत्ता
		राणाघाट(एससी)	परेश हलदर
		बनगांव(एससी)	स्वप्न मण्डल
		बैरकपुर	प्रदीप चौधरी
		बरासात	परेश घोष
		बशीरहाट	अजय बेन
		जयनगर(एससी)	डॉ. तरुण मण्डल
		मथुरापुर(एससी)	पूर्णचन्द्र नैया
		डायमण्ड हार्बर	अजय घोष
		जादवपुर	डॉ. अशोक कुमार सामंत
		कोलकाता दक्षिण	ज़ुबैर रब्बानी
		हावड़ा	सौमित्र सेनगुप्ता
		उलूबेरिया	मिनाती सरकार
		श्रीरामपुर	प्रो. मो. शानवाज़
		हुगली	प्रवण मजूमदार
		तमलुक	विवेक राय
		कांथी	मानस प्रधान
		घटल	अंजन जाना
		झारग्राम (एसटी)	राजीव मुदी
		मेदिनीपुर	तुषार जाना
		पुरुलिया	सुवर्ण कुमार
		बांकुड़ा	कबिता सिंह बाबू
		विष्णुपुर (एससी)	सदानन्द मण्डल
		वर्धमान पूर्व(एससी)	कालीचरण सरदार
		वर्धमान दुर्गापुर	सुनील कुमार पुरकैत
		आसनसोल	ए. एल. गुप्ता
		बोलपुर(एससी)	प्रो. विजय दलुई
		वीरभूम	आएशा खातून

● लेफ्ट यूनाइटेड फ्रण्ट द्वारा समर्थित उम्मीदवार जिसमें एसयूसीआई (सी) भी एक घटक है (केरल में आरएमपी, एसयूसीआई(सी) और एमसीपीआई(यू) को लेकर गठित हुए लेफ्ट यूनाइटेड फ्रण्ट (एलयूएफ) द्वारा अन्य 12 संसदीय क्षेत्रों से उम्मीदवार खड़े किये जा रहे हैं और बाकी दो क्षेत्रों में आजाद उम्मीदवारों को समर्थन दिया जा रहा है।)

आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में विधान सभा में एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के उम्मीदवारों को जितायें

क्र.सं.	राज्य	विधान सभा क्षेत्र	उम्मीदवार
1.	आन्ध्र प्रदेश	खैराताबाद	ई. हेमलता
		विशाखापट्टनम पूर्व	एस. गोविन्दराजुलू
		अनन्तपुर (अर्बन)	डी. राघवेन्द्र
		हिन्दुपुर	एम. बसवाराजू
2.	उड़ीसा	आनन्दपुर (एससी)	मिनाती जाना
		जोशीपुर(एसटी)	शम्भूनाथ नायक
		करंजिया(एससी)	जमुना समद
		बिन्झारपुर (एससी)	राधाबल्लब मल्लिक
		धर्मशाला	अक्षय कुमार दास
		तालचेर	प्रह्लाद चन्द्र साहू
		अंगूल	मन्दोदरी राऊल
		छेंदीपाड़ा (एससी)	भरत कुमार नायक
		बीरमहाराजपुर	नित्यानन्द मल्लिक
		बरबाटी-कटक	प्रतापचन्द्र मिश्रा
		चौद्वार-कटक	गणेश कुमार त्रिपाठी
		कटक सदर	राजकिशोर मल्लिक
		अऊल	डॉ. अबनी कुमार दास
		पीपीली	सुभाष बराल
		रणापुर	कृष्णचन्द्र महापात्र
		गोपालपुर	पी. शिव प्रसाद रेड्डी
		कोरापुट(एससी)	रामा बारिक

आगामी लोकसभा चुनाव में

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के उम्मीदवारों को वोट दें

चुनाव चिन्ह गिलास

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) की ओर से कॉ. सत्यवान द्वारा 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग, नई दिल्ली-5 से संपादित व प्रकाशित तथा परम्परा प्रिंटिंग प्रेस, बी-70/83, इण्डस्ट्रियल एरिया, लॉरेंस रोड, दिल्ली-35 से मुद्रित। दूरभाष : 011-25726631, Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com